

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर ४०० २०४

प्रकरण क्रमांक : /2015-निगरानी

11/3792-I-15

- 1- अतिश तिवारी उर्फ विट्टू पत्र श्री दीपक तिवारी, आय 23 वर्ष
- 2- राकेश कुमार तिवारी पत्र स्व० श्री/मरेशकुमार तिवारी उर्फ हकूजी तिवारी, आय 46 साल, व्यवसाय कृषि
- 3- शरद तिवारी पुत्र कैलाश तिवारी, आय 38 वर्ष व्यवसाय-कृषि
- 4- प्रवीण तिवारी पत्र श्री शम्भूदयाल आय 30 वर्ष, व्यवसाय-कृषि निवासीगण - मातापूरा विरोज चौराहा गुज बासोदा जिला विदिशा

----निगरानीकतगिण

काम

डाक्टर रमेशगुप्ता पत्र सुनीय श्री डी.सी.गुप्ता
निवासी मेन बसेठ रोड गुज बासोदा जिला
विदिशा म प्र. --रेस्योडेन्ट

निगरानी अन्तर्ति धारा 50 म 0 प्र० भू- राजस्व सहित
विरुद्ध अदिश दिनांक 29.10.2015 न्यायालय तहपोलदार बासोदा
जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 8/ए-70/14-15 व माम ले सुमेश
गुप्ता काम अतिश तिवारी मे पोरिते अदिश के विरुद्ध।

=====

माननीय न्यायालय

निगरानीकतगिण की ओर मे निगरानी निम्न प्रकार प्रस्त

सक्षिप्त तथ्य :-

R.Bh

श्री आर.बी. शर्मा अफिमामक
द्वारा दिनांक 20-11-15 को
पुस्तक

~~फैसल~~
S. 8 20-11-15

R.Bh
20-11-15

R.Bh

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

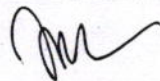
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3792-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
1.12.2015	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आर० बी० शर्मा उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में तहसीलदार तहसील बासोदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 8/अ-70/14-2015 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.10.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया है आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वही तथ्य दोहराये गये है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेख किया गया है । उनके द्वारा बताया गया है कि म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 का आवेदन निरस्त कर दिया गया है तथा उनके द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आवेदन किन कारणों से निरस्त किया गया है । अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के साथ तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत धारा-250 के आवेदन पत्र की सत्यप्रतिलिपि इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है । अभी तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है तथा वहां पर उभयपक्ष के कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं । तथा उनको</p>	

fas



वहां। पर अपनी बात कहने का अवसर भी है ।

3- अतः निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है । पक्षकार सूचित हों । इस न्यायालय के आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे । प्रकरण दा0 द0 हो ।

401


सदस्य